THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) and (b). A proposal of the ONGC was approved by the Government in November 1979 for the purchase of a Multipurpose Support Vessel (MSV) at a cost of Rs. 20.83 crores to be covered under Dutch Credit, from M/s. Ocean Inchape Limited, UK. However, M/s. Ocean Inchape Limited subsequently withdrew their offer and as such at present the ONGC is *not* purchasing any Multipurpose Support Vessels from M/s. Ocean Inchape Limited, London.

(c) and (d) The tenders for the purchase of the MSV were invited by ONGC from three countries namely, U K , Netherlands and France as per the directive of the Government of India This was done with a view to utilise the availability of credit/grant from these countries

(e) The offer of M/s. Ocean Inchape Limited was accepted by ONGC after satisfying itself about the capability of M/s. Ocean Inchape Limited and the Dutchyard where the MSV was to be fabricated.

Progress of work on Buxer Koelwar Embankment in Bihar

*845 SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether even one fourth work of Buxer-Koelwar embankment on right side of Ganges in Bihar has not yet been completed; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDAY): (a) and (b). The State Government has reported that out of the total earthwork of 171.52 lakh cubic metre required for the Buxer Koelwar Embankments, the quantity of work done to the end of June 1980 is 77.27 lakh cubic metre.

Bedthi Power Project in North Canara, Karnataka

*850. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state what is the estimate of the Bedthi Power Project and what is the stage of the execution of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Bedthi (Gangavali) Hydroelectric Project Stage—I (2x105 MW), has been approved by the Planning Commission in April, 1979 for an estimated cost of Rs. 13924 lakhs, including transmission lines and receiving stations. Presently, infrastructure works and detailed investigations for taking up the construction of the various components are in progress.

कोयला उद्योग में पूंजी निवश

*851. **श्री मूल चन्द डागा**: क्या ऊर्जा और कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) कोयला उद्योग का राष्ट्रीय करण कब हुआ था और सरकार द्वारा अब तक इसमे कितनी पूजी लगाई गई है ;

(ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड और कोल इडिया लिमिटेड मे सरकार द्वारा अब तक कितनी पूजी लगाई गई है और दोनो कपनियों के कृत्य क्या है और उन दोनो के बीच किस प्रकार का समन्वय स्थापित है ;

(ग) कोयला खान प्राधिकरण तथा कोल इडिया लिमिटेड मे गैर सरकारी एजेसियो द्वारा कितनी पूजी लगाई गई है ; और

(घ) क्या वे दोनो कम्पनिया पिछले बहत से सालो से घाटे पर चल रही है और यदि हा, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख). कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण दो चरणो में किया गया था अर्थात (1) 1-5-1972 को सारी कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारत कोकिंग कोल

लि० के अधीन कर दिया गया था ; (2) 1-5-1973 को बाकी सभी कोयला खानों का राष्ट्रीय करण कर दिया गया था और उन्हें सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी "कोयला खान प्राधिकरण लि०" के अधीन कर दिया गया था । इस कम्पनी में उस समय विद्यमान एक अन्य सरकारी कंपनी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का भी विलय कर दिया गया था । नवम्बर, 1975 में राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग का पुनर्गठन किया गया और कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० का स्वरूप बदल कर "कोल इंडिया लि०" नामक एक धारक कंपनी स्थापित की गई जिसकी पांच सहायक कम्पनियां बनाई गयीं । सहायक कम्पनियों के नाम थे—भारत कोकिंग कोल लि०, बैस्ट्रन कोलफील्डस लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड लि०, ईस्ट्रन कोलफील्ड लि० और केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान । चूंकि कोयला खान प्राधिकरण लि० की, भारत कोकिंग कोल लि० का भी विलय करके, कोल इन्डिया लि० नामक कम्पनी बना दी गई थी इस लिए कोयला खान प्राधिकरण लि० और कोल इंडिया लि० के बीच किसी समन्वय का प्रश्न ही नहीं उठता । कोल इन्डिया लि० राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला भंडारों के विकास और उपयोग के लिए उत्तरदायी है ; इस काम में उसे दुबारा न मिल सकने वाली प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और कोयला खान मजदूरों की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखना पड़ता है । भारत सरकार ने 31-3-1980 तक कोल इंडिया लि० में, जो कुल पूंजी लगाई है वह लगभग 1343.31 करोड़ रुपये है ।

(ग) कोल इंडिया लि० में किसी गैर सरकारी एजेंसी का कोई रुपया नहीं लगा है ।

(घ) कोल इंडिया लि० को घाटा होने का मुख्य कारण सरकार द्वारा नियत कोयले की वह अलाभकारी कीमतें थी जो लगभग चार वर्ष तक अपरिवर्तित रहीं । इसके साथ ही घाटा होने का अन्य कारण यह रहा कि मजदूरी में तथा उत्पादन के अन्य साधनों की लागत में वृद्धि होती रही और दूसरी ओर बिजली की कमी, डीजल और विस्फोटक पदार्थों की कमी, मजदूरों की अनुपस्थिति, कानून और व्यवस्था की समस्या तथा कुछ अन्य समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी होती रही ।

Pending Applications for issue of new Domestic Gas Agency

*852. SHRI DAULATSINHJI JADEJA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) the number of applications for new domestic gas agencies are pending with the Government as on 31st December, 1979;

(b) whether any new agency has been allotted during the year 1980;

(c) if so, when and to whom; and

(d) the criteria adopted for alloting such agencies?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Retail outlet dealerships/distributorships including cooking gas agencies are awarded by respective oil marketing companies and not by Government. Appointment of dealers/distributors is made by them in accordance with the guidelines laid down for this purpose. After selection of the dealer is completed from among the applicants, the remaining applications are deemed rejected. No record is maintained as regards individual requests made to the Government.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

(d) According to the policy guidelines currently in force, 25 per cent of all agencies are reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, 10 per cent for Defence personnel dis-